

छत्तीसगढ़ के ‘रक्षक’ मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर डंका : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिला प्रतिष्ठित SKOCH ‘गोल्डन अवार्ड’

रायपुर (जनता के गोठ)। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आयोग द्वारा तैयार किए गए अभिनव ‘रक्षक’ कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित ‘SKOCH गोल्डन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

दिग्गजों की मौजूदगी में मिला राष्ट्रीय सम्मान- पुरस्कार वितरण समारोह में व्हाट्सएप रूप के चेयरमैन समीर कोचर द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर

प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुश्री सुनीता नारायण, पापुलेशन फउंडेशन ऑफ इंडिया की सुश्री पूनम मुटेरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री संजय कुमार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव श्री भरत लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया काफी कड़ी थी। जूरी के समक्ष ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम पर दिए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण और गहन परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया।

क्या है ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम? - पूरा नाम: पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (PGDPCR)। - अवधि व न्यूनतम योग्यता: 1 वर्षीय (2 सेमेस्टर) डिप्लोमा कोर्स, जिसके लिए



न्यूनतम योग्यता स्नातक (Graduation) रखी गई है। - प्रैक्टिकल व फील्ड मॉडल: छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे। वे बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड केयर संस्थानों और स्वीच्छिक संगठनों के साथ सीधे जुड़कर फील्ड वर्क, केस स्टडी और लाइव प्रोजेक्ट्स पर कार्य

करेंगे।

- प्रमुख विषय: पाठ्यक्रम में पॉक्सो (POCSO) एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE 2009) और शासकीय पुनर्वास योजनाएं शामिल हैं।

विश्वविद्यालयों में लागू होगा कोर्स, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर- यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उनके बोर्ड/परिषद की अनुमति से प्रांरभ किया जा रहा है। इस नवाचार से बाल संरक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होंगे, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

ग्राम सांकरा में उत्साहपूर्वक सुना गया पीएम मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम : 138वें एपिसोड में बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण

सांकरा/रायपुर। ग्राम सांकरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड का सामूहिक प्रसारण आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के विचारों, देश के विकास और समाज हित से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुना।

जन-जन को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का माध्यम: रवि सिंगौर- कार्यक्रम के उपरांत भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच रवि सिंगौर ने कहा कि ‘मन की बात’ केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे नागरिकों के प्रयासों को उजागर करते हैं और जनभागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण रहे मौजूद इस सामूहिक श्रवण कार्यक्रम में गांव के जनप्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक



भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से: - रवि सिंगौर (भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच) - छोटू यादव (बृथ अध्यक्ष) - मनहरण सिंगौर (सांसद प्रतिनिधि) - तुलाराम सिंगौर एवं शुभम जांगड़े (पंच) - कामता सिंगौर, पिंटू यादव, विकास सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू ने अपने जन्मदिन पर फलदार पौधरोपण किया

उतई की जनता और पुरे छत्तीसगढ़ के लोगों से वृक्षारोपण करने हेतु की अपील

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

उतई - नगर पंचायत उतई के पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू ने शनिवार को अपने जन्मदिन के खास अवसर पर एक सराहनीय पहल की। उन्होंने उतई स्थित विश्राम गृह परिसर में चिरई जांम और बादाम के फलदार पौधों का रोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश दिया।

पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने द्वारिका साहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान फलदार पौधे लगाने की इस पहल की सभी ने सराहना करते हुए कहा कि जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसरों पर पौधरोपण करना प्रकृति को सहेजने की दिशा में एक अनुरूपणीय कदम है। इस अवसर पर नगर पंचायत उतई के उपाध्यक्ष शिवनारायण देशमुख, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी, प्रहलाद वर्मा, सोनू राजपूत, खुशी साहू, राकेश साहू, नगर साहू समाज अध्यक्ष किशोर



साहू, शिक्षक गिरीश साहू, सेल्फ संपर्क खिलाेश मारकंडे, उपसरपंच राकेश साहू, पत्रकार बलराम वर्मा, किशन हिरवानी, मुकेश साहू, डोमन हिरवानी,नरेंद्र साहू ,भावेश साहू, धनंजय नेताम, कैलाश देवांगन, संतोष बंधोले, देवनारायण ठाकुर, ऋषि साहू, वीरेंद्र गोस्वामी, गुलशन शर्मा, पदुम ठाकुर, टीकम डौंडे, श्रवण यादव, योगेश माण्डले, सुरेखा साहू, चंद्र प्रभा, सुनीति

साहू, सरोज ठाकुर, हुलसी वर्मा, रामशिला नेताम, ललित साहू, मन्नू गोस्वामी, कुशल साहू, धर्मेन्द्र साहू, युगल साहू, झमन यदु, कुंवर बाई, सकून साहू, स्नेहा डाहरिया, शुभम बंधोले, माताओं, अधिभावकों, स्वसहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। ‘आंगन मिलन सेवा’ का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय

तरेगांव जंगल और दलदली क्षेत्र के बेगा-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आंगन मिलन सेवा से जुड़े परिवार

पोषण थाली, स्वास्थ्य जांच, न्योता भोज और योजनाओं की जानकारी बनी आकर्षण का केंद्र

कवर्पा (जनता के गोठ)। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बेगा बहुल क्षेत्र तरेगांव जंगल और दलदली क्षेत्र में आज सेवा, पोषण और जनभागीदारी का अनूठा संगम देखने को मिला। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत क्षेत्र के सभी 135 आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘आंगन मिलन सेवा’ का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस आयोजन में बच्चों, माताओं, अधिभावकों, स्वसहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। ‘आंगन मिलन सेवा’ का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय

से जोड़ते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान ‘विकसित भारत-2047’ के नागरिक संकल्प से भी लोगों को जोड़ा गया। ‘मेरी पौष्टिक थाली’ ने दिया सुपोषण का संदेश- आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय खाद्यान्न, ताजी हरी सब्जियों और फलों से तैयार ‘मेरी पौष्टिक थाली’ आकर्षण का केंद्र रही। इसके माध्यम से बच्चों और माताओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी गई। केंद्रों में पोषण संबंधी जागरूकता गतिविधियों के साथ कुपोषण दूर करने का संदेश भी दिया गया।

स्वास्थ्य जांच से लेकर टीकाकरण तक मिली सेवाएं- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यकतानुसार टीकाकरण किया गया। बच्चों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। जनभागीदारी से ‘न्योता भोज’ का आयोजन कर



बच्चों को पौष्टिक भोजन, फल एवं मिठाइयां वितरित की गईं। मेहंदी, रंगोली और स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता ने बढ़ाई रौनक- महिलाओं और युवतियों के लिए मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं ‘स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता’ के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति परिवारों को प्रोत्साहित किया गया। सुपोषित

बच्चों और उनकी माताओं को सम्मानित कर बेहतर पोषण के लिए प्रेरित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वालों का हुआ सम्मान- कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं श्रीपत्त प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी

अमले का उत्साहवर्धन हुआ और समुदाय के बीच उनकी भूमिका को सम्मान मिला।

योजनाओं के लाभ से जुड़ीं माताएं, नए हितग्राहियों का पंजीयन- महतारी वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महतारी वंदना योजना की राशि का उपयोग करने वाली सजग माताओं को ‘पोषण शक्ति सम्मान’ प्रदान किया गया। साथ ही पात्र नवीन हितग्राहियों का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मौके पर पंजीयन भी किया गया।

खिलौना बैंक के लिए समुदाय ने बढ़ावा सहयोग का हाथ- बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘खिलौना बैंक’ की समुद्ध करने के लिए समुदाय को खिलौने एवं खेल सामग्री दान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए और अधिक आनंददायी एवं सीखने का बेहतर स्थान बनाने का संदेश दिया गया।

पेड़ से फंदे पर लटका मिला युवक का शव , क्षेत्र में फैली सनसनी

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

पाटन - पाटन क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक द्वारा फंसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान घौराभाव निवासी कोमेश ठाकुर के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, कोमेश ठाकुर का शव उसके गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित करहीखार पांच पोंगा के पास एक अर्जुन के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।



पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया जाएगा और पंचनामा की कार्यवाई के बाद आगे की वैधानिक जांच की जाएगी। आत्महत्या के कारणों का फिंत्हाल खुलासा नहीं हो सका है।

‘साहेब हैं तो आपदा में भी आस है’ : आरंग में बाढ़ प्रभावितों के लिए देवदूत बने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सुरक्षित भवनों में कराया शिफ्ट; बांटी राहत सामग्री

आरंग/रायपुर (जनता के गोठ)। आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ की स्थिति के बीच कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुट गए हैं। नगर पंचायत समोदा के नदी तटीय क्षेत्रों और ग्राम पंचायत कागदेही के बाढ़ प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने तत्काल कदम उठाकर सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया है।

महाविद्यालय और सामुदायिक भवन बने राहत शिविर

बाढ़ से घिरे परिवारों को तत्काल समोदा के शासकीय महाविद्यालय भवन एवं सामुदायिक भवन में सुरक्षित रूप से ठहराया गया है। जहां प्रशासन और स्थानीय



जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उनके रहने, भोजन और आवश्यक सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की गई है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने के बाद प्रभावितों को दैनिक उपयोग की सामग्री, राशन, कपड़े, गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान वितरित किए गए। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने स्वयं राहत शिविरों का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों का हाल-चाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं।

आपदा में सेवा ही पहला संकल्पक्र : मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

प्रभावित परिवारों से संवाद करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा, “आपदा के समय सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान और उनकी सुरक्षा है। संकट की इस घड़ी में कोई भी परिवार खुद को अकेला न

समझे। मैं और पूरा प्रशासन आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं।” उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राहत शिविरों में रुके परिवारों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा सुविधा और गर्म कपड़ों की आपूर्ति में कोई ढिलाई न बरती जाए।

ग्रामीणों ने जताई राहत, लगातार रखी जा रही नजर

आपदा के समय तुरंत मिली सहायता और मंत्री के संवेदनशील रवैये से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि संकट के समय क्षेत्रीय विधायक की इस सक्रियता ने उन्हें संबल दिया है। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पाटन में बारिश का कहर , खारून नदी – नाले उफान पर

बाढ़ के बीच प्रशासन अलर्ट, एसडीएम उत्तम ध्रुव ने नदी किनारे गांवों का किया दौरा

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। पाटन अंचल में लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। वहीं बस्तर संभाग में भारी बारिश के चलते कई बांधों के गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बारिश और संभावित बाढ़ के बीच पाटन में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है।

एसडीएम उत्तम ध्रुव ने नदी किनारे बसे गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने तथा अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की। प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की हिदायत दी जा रही है।

भोथली में सख्त्त की टीम मैदान में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में



राहत और बचाव के लिए SDRF की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। भोथली क्षेत्र में सख्त्त जवानों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और निचले इलाकों की स्थिति पर बनी हुई है। लगातार बारिश के बीच ग्रामीणों से प्रशासन



की अपील है कि वे नदी, नाले और जलभराव वाले स्थानों के पास जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। मेडिकल स्टफ्टैयार लगातार बारिश के बिगड़ते हालात को देखते हुए मेडिकल टीम ने पूरी तैयारी, डॉक्टरों के साथ मेडिकल की टीम एंबुलेंस सहित पूरा स्वास्थ्य अमला मौजूद

सिलयारी में ‘आँगन उत्सव’ : विधायक अनुज शर्मा ने बच्चों को परोसा ‘न्योता भोज’, कार्यक्रमों को बताया ‘राष्ट्र निर्माता’

धरसीवाँ को कुपोषण मुक्त बनाने का लिया संकल्प, बच्चों को बांटी खेल सामग्री

राष्ट्रीय ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ग्राम सिलयारी में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम

सिलयारी/धरसीवाँ (जनता के गोठ)। राष्ट्रीय ‘सेवा संकल्प अभियान’ (17 सितंबर से 17 अक्टूबर) के तहत धरसीवाँ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलयारी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-06 (बोहरही धाम मंडल) में ‘आँगन उत्सव’ का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और बच्चों के साथ आत्मीय क्षण बिताए।

बच्चों के बीच पहुंचे विधायक, खुद परोसा ‘न्योता भोज’ आयोजन का मुख्य आकर्षण ‘न्योता भोज’ रहा। विधायक अनुज



शर्मा ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर बातचीत की। विधायक को अपने बीच पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आंगनबाड़ी बहनें कर्मचारी नहीं, असली राष्ट्र निर्माता- जनसमूह और कार्यकर्ताओं को संवेगित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा, “आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें केवल कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि

हमारे समाज की असली ‘राष्ट्र निर्माता’ हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को पहली बार किसी सुरक्षित हाथ में सौंपती है, तो वो हाथ आंगनबाड़ी बहनें का होता है।” उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की पहली मुस्कान, उनका पहला खेल और जीवन का पहला अक्षर आंगनबाड़ी बहनें की देखरेख में ही निखरता है। इनका यह योगदान किसी तपस्या से कम

नहीं है। धरसीवाँ से कुपोषण मिटाने का संकल्प क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए विधायक ने कहा, “हमारी सरनकार महिला एवं बाल विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि धरसीवाँ विधानसभा का कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। इस अभियान के

मार्थम से हम हर बच्चे को एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं।” खेलकूद से होता है सर्वांगीण विकास उत्सव के दौरान बच्चों को खेलकूद सामग्री और उपहार वितरित किए गए। विधायक शर्मा ने बताया कि बचपन में खेलकूद केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों में अनुशासन, स्वस्थ शरीर और टीम भावना का विकास करता है। कार्यक्रम में ये प्रमुख जन-प्रतिनिधि रहे मौजूद कार्यक्रम में भाजपा जिला सांठन प्रभारी सुरेंद्र पाटनी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम कुमार नारंग, पिछड़ा वर्ग आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रकांती वर्मा, सविता चंद्राकर, बोहरही धाम मंडल अध्यक्ष हरि शंकर वर्मा, महामंत्री रूखमणी शिवारे, अशोक साहू, रूखमणी साहू और मधुसूदन कश्यप सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

वडनगर से वाराणसी तक भाजयुमो की ‘सेवा संकल्प बाइक रैली’: छत्तीसगढ़ के 5 रूटों से होकर गुजरेगी यात्रा, रायपुर में 29 को होगा ‘लाभार्थी सम्मेलन’

रायपुर (जनता के गोठ)। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) द्वारा ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से उनकी संसदीय कार्यस्थली काशी (वाराणसी) तक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति, सामाजिक दायित्व और संगठनात्मक एकता का संदेश लेकर निकल रही यह यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने जानकारी दी कि प्रदेश में इस यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत किया जाएगा और सेवा संकल्प का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

29 सितंबर को रायपुर में ‘लाभार्थी सम्मेलन’

प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बताया कि 27 सितंबर से बस्तर के सभी जिलों से सैकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ता रैली के रूप में रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के साथ-साथ स्वच्छता अभियान और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हुए रायपुर पहुंचेगी। 29 सितंबर को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले ‘लाभार्थी सम्मेलन’ में प्रदेश भर के युवा मोर्चा कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे।

छत्तीसगढ़ में 5 अलग-अलग रूटों से तय होगा सफ़र
सेवा संकल्प यात्रा को छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख रूटों में विभाजित किया गया है:

- रूट 1 (दंतेवाड़ा से रायपुर): बस्तर के दंतेवाड़ा से



शुरू होकर यह बाइक रैली सीधे रायपुर पहुंचेगी।

- रूट 2 (महाराष्ट्र-राजनांदगांव से झारखंड): 28 सितंबर को महाराष्ट्र के रास्ते यह यात्रा राजनांदगांव जिले में प्रवेश करेगी। 7 दिनों तक दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा,

कोरबा, रायगढ़ और जशपुर जिलों का भ्रमण करने के बाद यह रैली झारखंड की ओर प्रस्थान करेगी।

- रूट 3 (मध्य प्रदेश-चिल्पी घाटी से उत्तर प्रदेश): 29 सितंबर को मध्य प्रदेश की ओर से चिल्पी घाटी होकर कबीरधाम जिले में प्रवेश होगा। यह यात्रा कवर्धा, पंडरिया, गौरला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।

- रूट 4 (जनकपुर-एमसीबी जिला): 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से एक यात्रा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (खूँट) जिले के जनकपुर पहुंचेगी। यहां रात्रि

विश्राम के बाद यात्रा पुनः मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ओर लौट जाएगी।

- रूट 5 (मनेन्द्रगढ़ से उत्तर प्रदेश): 1 अक्टूबर की शाम को एक अन्य यात्रा मनेन्द्रगढ़ पहुंचेगी, जो 3 दिनों में कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी।

युवाओं में राष्ट्रसेवा और संगठन का संकल्प
भाजयुमो के अनुसार, इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर राष्ट्रसेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और सांगठनिक मजबूती की भावना को गहरा करना है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में यात्रा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

चिल्पी घाटी में 9 घंटे लगा रहा जाम, रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में आवागमन बाधित से लोग परेशान, तीन ट्रक सड़क में दुर्घटनाग्रस्त होने से लगी वाहनों की लंबी कतार



कवर्धा(जनता के गोठ)। कबीरधाम जिले के चिल्पी में तीन ट्रक के बीच एक्जिडेंट से मार्ग अवरूद्ध हो गया है जिसमें छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में रविवार को सुबह 7 बजे 3 बजे तक लगभग 7 घंटे जाम कि स्थिति बनी रही है, दुर्घटना के कुछ ही घंटों

में सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जिससे यात्री बस , कार समेत दर्जनों वाहनों की लंबी कतार लग गई 2। दरअसल चिल्पी थाना क्षेत्र के दुलदुला गांव के पास रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में जबलपुर के ओर रायपुर जा रही एक ट्रक बीच सड़क पर खड़ी थी इस दौरान दो अलग-अलग ट्रक

क्रासिंग के दौरान दोनों ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क पूरी तरह जाम हो गया इससे सड़क अवरूद्ध हो गया है। घटना के बाद चिल्पी पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाई तब जाकर तीन बजे के बाद रास्ता बिलयर हो पाया और लोग आवागमन कर पाए।

तेज बहाव में फंसा युवक सुरक्षित रेस्क्यू

दुर्ग। लगातार बारिश के बीच कोकडी नाला पुल पर पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सहित बहकर पेड़ के सहारे फंसे युवक को उर्तई पुलिस और डायल-112 टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। ग्राम पव्वारा निवासी लोकेश्वर साहू 25 सितंबर को मोटरसाइकिल से पव्वारा से खमहरिया जा रहे थे। कोकडी नाला पुल पर पानी का बहाव तेज होने के कारण वह मोटरसाइकिल सहित बह गए। किसी तरह एक पेड़ के सहारे पहुंचकर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही थाना उर्तई की टीम निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रशिक्षु उप निरीक्षक दीपक कुमार तथा डायल-112 टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सावधानीपूर्वक युवक तक पहुंच बनाकर उसे पेड़ के सहारे से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। रेस्क्यू टीम में प्रधान आरक्षक आशीष सिंह, आरक्षक राजीव दुबे, दीपक जॉन और डायल-112 चालक भी शामिल रहे। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी, नाला और पुल-पुलिया में तेज बहाव होने पर उन्हें पार करने का जोखिम न उठाएं। आपात स्थिति में तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम या डायल-112 को सूचना दें।

लुनिया परिवार ने नेत्रदान कर प्रस्तुत किया मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण

कवर्धा(जनता के गोठ)। जिले में मानव सेवा और सामाजिक जागरूकता की मिसाल पेश करते हुए लुनिया परिवार ने स्वर्गीय भीषम चंद लुनिया के निधन उपरांत उनकी आँखों का दान कर समाज के समक्ष एक अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में नेत्रदान, अंगदान एवं देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला प्रेरणादायी कदम भी है। मृत्यु उपरांत नेत्रदान की प्रक्रिया को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार संपन्न कराया गया। इस कार्य में नेत्र सर्जन डॉ. क्षमा चोपड़ा, डॉ. आयुषी साहू, स्टाफनर्स रमेश्वरी नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जाँय एवं लक्ष्मीकांत राजपूत तथा वाहन चालक रिजवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र तुरे एवं डीपीएम अनुपमा तिवारी के निदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपादित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि नेत्रदान, अंगदान और देहदान जैसे मानव कल्याणकारी कार्यों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करें। मृत्यु के बाद किया गया

दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में नई आशा और रोशनी ला सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी सहित सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से नेत्रदान, अंगदान एवं देहदान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ऐसे सामाजिक एवं मानवीय प्रयास समाज में सेवा, संवेदना और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं।

सुतिया पाठ नहर एवं जगमड़वा जलाशय योजना से जुड़े 29 किसानों को एसडीएम ने प्रदान किया गया मुआवजा राशि का चेक

कवर्धा(जनता के गोठ)। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की विकास योजनाओं से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में सुतिया पाठ नहर विस्तारीकरण तथा जगमड़वा जलाशय योजना के अंतर्गत संबंधित 29 किसानों को रजिस्ट्री उपरांत मुआवजा राशि के चेक प्रदान किया गया।

सुतिया पाठ नहर विस्तारीकरण योजना के 23 किसानों को मिला लाभ- सुतिया पाठ नहर विस्तारीकरण योजना अंतर्गत ग्राम खैरबना एवं सिलहटी के कुल 23 किसानों को भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मुआवजा राशि के चेक प्रदान किए गए। किसानों को नियमानुसार उनकी भूमि के एवज में राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे



उन्हें आर्थिक सहायता मिली है।

जगमड़वा जलाशय योजना के 6 किसानों को प्रदान किए गए चेक- इसी प्रकार जगमड़वा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य अंतर्गत ग्राम सहसपुर लोहारा के 6 किसानों को भी रजिस्ट्री उपरांत मुआवजा राशि के चेक प्रदान किए गए। संबंधित किसानों को भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार भुगतान किया गया।

विकास कार्यों के साथ किसानों के हितों का संरक्षण- सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से

शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ हितग्राहियों और किसानों को नियमानुसार मिलने वाले लाभ एवं अधिकार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नहर एवं जलाशय जैसी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ किसानों को उनकी भूमि के संबंध में नियमानुसार मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विकास कार्यों के साथ प्रभावित किसानों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

उतई सहकारी समिति की आमसभा में किसानों को बड़ी सौगात

धनतेरस पर मिलेगा 12न्न
लाभांश. विधायक ललित चंद्राकर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन की मौजूदगी में वार्षिक आय-व्यय प्रस्तुत ।

उतई - किसानों की समृद्धि को बताया विकास का आधार

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

उतई - सेवा सहकारी समिति उतई में वार्षिक आमसभा का आयोजन शुक्रवार को सामुदायिक भवन उतई में आयोजित किया गया। आमसभा के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर थे। अध्यक्षता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने की। विशेष अतिथि जिला पंचायत सभापति श्रीमति श्रद्धा साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष सरस्वती साहू, नगर पंचायत उपाध्यक्ष



शिवनारायण देशमुख, भाजपा उतई मंडल अध्यक्ष श्रीमति शीतला ठाकुर, भाजपा उतई मंडल महामंत्री द्रय प्रवीण यदु, चंडु देवांगन, डुमरडीह सरपंच धर्मेन्द्र बंजारे, उमरपोटी सरपंच विजेन्द्र साहू, खोपली सरपंच मंजू वर्मा थी।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बलराम की पूजा अर्चना कर किया गया। प्राधिकृत अधिकारी पत्तेलाल वर्मा ने स्वागत भाषण पर 12 मि किसानों को धनतेरस पर सही प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा

की। समिति प्रबंधक गिरधर सोनी ने वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि राज्य की विष्णुदेव सरकार किसानों की हितैषी है। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 21 क्विंटल धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने का फैसला किया। जो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि धरती में सबसे ज्यादा पूजनीय किसान हैं। जो अपना पसीना बहाकर धरती से सोना उगाते

हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि धरती के भगवान किसान हैं। जो अपने मेहनत से सबका पेट भरते हैं। किसान खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। इसलिए राज्य सरकार किसानों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाती है। धान खरीदी भी किसानों के लिए वरदान सामान है। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट किसानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश साहू व आभार गोविंद साहू ने किया।

कार्यक्रम में पार्षद गण सतीश चंद्राकर, लक्ष्मीनारायण साहू, खूबीराम साहू, सोनू राजपूत, संगीत रजक, रूपेश पारख, फलेन्द्र सिंह राजपूत, शुभम वर्मा, अश्वनी वर्मा, चंद्रशेखर चंद्राकर, सोहन रिगरी, राजकुमार साहू, धनश्याम चंद्राकर, विजय चंद्राकर, रूप्नारायण बघेल, लोकनाथ साहू, जयंत साहू, खोवालाल देशलहरे, गोविंद साहू, गोपाल साहू, टुमन चंद्राकर, गोरखनाथ साहू, तिलक साहू, प्रहलाद साहू सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे।

फार्मासिस्टों की आवाज को मजबूती देने वाले सूरज यादव सम्मानित

बिलासपुर में राज्य स्तरीय समारोह में मिला सम्मान, संगठन और फर्मासिस्ट साथियों के हित में उत्कृष्ट योगदान की हुई सराहना

बलरामपुर (जनता के गोठ) : विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय फर्मासिस्ट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा बिलासपुर स्थित एलसीआईटी कैंपस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेशभर से पहुंचे फर्मासिस्टों और संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में फर्मेसी क्षेत्र एवं संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले सदस्यों का सम्मान किया गया।

समारोह में बलरामपुर जिले के सूरज यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय फर्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ को संगठन को मजबूती देने तथा फर्मासिस्ट साथियों के हित में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

सूरज यादव के सम्मान को



बलरामपुर जिले के लिए भी गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के साथ फर्मासिस्ट साथियों के मुद्दों को मजबूती से उठाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनके योगदान की कार्यक्रम में सराहना की गई।

सम्मान ने बढ़ाया हौसला, संगठन के प्रति समर्पण का लिया संकल्प

सम्मान प्राप्त करने के बाद सूरज यादव ने एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों एवं फर्मासिस्ट

साथियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए केवल स्मृति चिन्ह नहीं, बल्कि फर्मासिस्ट समाज के लिए और अधिक मजबूती से कार्य करने की जिम्मेदारी और प्रेरणा है।

उन्होंने कहा कि फर्मासिस्टों की एकजुटता, सम्मान और हितों का आवाज को मजबूत करने के लिए संगठन के साथ पूरी प्रतिबद्धता से कार्य जारी रहेगा।

फर्मासिस्टों की भूमिका पर हुआ अंश

कार्यक्रम में स्वास्थ्य व्यवस्था में फर्मासिस्टों की महत्वपूर्ण

भूमिका, मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता तथा फर्मेसी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राज्य स्तरीय आयोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फर्मासिस्टों को सम्मानित कर उनके योगदान को पहचान दी गई।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस का यह आयोजन केवल सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेशभर के फर्मासिस्टों को संगठनात्मक एकजुटता और अपने पेशे के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दे गया।

संपादकीय

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में आंतरिक मतभेदों और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सदस्यों के बीच अलग राय और विचार होना बातचीत का एक सामान्य हिस्सा था और सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। कामकाज के तरीकों को लेकर चुनाव

आयोग हाल के बरसों में लगातार विवादों में रहा है। विपक्ष का उस पर अविश्वास इतना गहरा शायद कभी नहीं रहा, जहां उसके तमाम फैसलों पर संदेह जताया गया। ऐसे में आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा जो खुलासा हुआ है, वह गंभीर सवाल खड़े करता है। दोनों आयुक्त आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त से सहमत हुए या नहीं, इससे बड़ा मुद्दा है कि स्पेशल इन्टेनशिव रिवीजन यानी एसआईआर जैसे

संवेदनशील मसले पर उनकी आपत्तियों पर क्या हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सदस्यों के बीच अलग राय और विचार होना बातचीत का एक सामान्य हिस्सा था और सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। आयोग का यह भी कहना है कि 10 महीने की कुछ आंतरिक टिप्पणियों को अलग करके देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। चुनाव आयोग के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके तक सही लगते हैं।

यह कतई जरूरी नहीं है कि किसी मामले में तीनों आयुक्तों की राय एक जैसी हो। संस्थान के भीतर असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अलग-अलग विचार सामने आने पर ही बेहतर विकल्प का रास्ता खुलता है।हालांकि विभिन्न विचारों का फायदा तभी मिलता है, जब उन्हें सुना जाए। आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि किन असहमतियों पर विचार हुआ, किनको स्वीकार किया गया और किन पर एक राय

बनाने की कोशिश हुई। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला रद्दक्र मतदाताओं के नाम हटाने-जोड़ने और उस डिजिटल सिस्टम से जुड़ा है, जिस पर इलेक्टोरल रोल निर्भर है। एसआईआर बेहद ही संवेदनशील मसला है। बिहार में इसकी शुरुआत से लेकर दिल्ली तक, कई बार इसे लेकर असंतोष जताया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में तो विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस घटना से विपक्ष के आरोपों को बल

मिलेगा और एसआईआर को लेकर शंका बढ़ेगी, बल्कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में दोबारा विश्वासघात चुनाव कराने की मांग कर ही दी है। जब इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जारी हो, तब इतने किंतु-परंतु ठीक नहीं हैं। जनता को पता हो। देश में स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे जरूरी आधार चुनाव आयोग है। जनता का भरोसा उस पर तभी मजबूत होगा, जब उसे पता हो कि संस्थान के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है।

हाल ही में अमेरिकी संसद द्वारा भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने सम्बंधी कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि, ये देश रूस से कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अमेरिका के अनुसार, इन देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात के चलते रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध करने की आर्थिक शक्ति प्राप्त हो रही है। जबकि, यूरोपीयन देश एवं अमेरिका स्वयं रूस से गैस एवं अन्य उत्पादों का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अर्थात, इन देशों द्वारा रूस से अन्य पदार्थों के आयात करने से रूस को कोई आर्थिक ताकत प्राप्त नहीं होती है, केवल भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात से रूस को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र अब पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो रहा है।

भारत को डराया नहीं जा सकता, यह नया भारत है



कोई आर्थिक ताकत प्राप्त नहीं होती है, केवल भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात से रूस को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र अब पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो रहा है। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का डर दिखा कर एवं भारत को दबाव में लाकर अमेरिका भारत से अपने मनमाफिक निर्णय करवा लेगा, तो आज की बदली हुई परिस्थितियों के बीच यह सम्भव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका एवं पूरे विश्व के सामने अब एक नया भारत खड़ा है। अमेरिका दरअसल चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले ताकि वह भारत को अपने कृषि एवं डेयरी उत्पाद निर्यात कर सके। यदि भारत अमेरिका के इस दबाव में आता है तो भारतीय किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और केंद्र सरकार भारत के किसानों के हितों की बलि किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। आज, संभवतः अमेरिका को भारत की अधिक आवश्यकता है क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देशों की श्रेणी में उच्च स्थान रखता है। साथ ही, भारत आज विश्व में विभिन्न उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है एवं आगे आने वाले समय में भारत की यही स्थिति लम्बे समय तक बनी रहने वाली है। भारत आज विश्व के अन्य उत्पादक देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार है।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज विश्व में बड़े देशों के बीच सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जापान ने भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। और तो और, अब अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग में सुधार करने पर विचार करने को मजबूर हो रही हैं। हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, जेफरीज ने भी अपने पूर्व अनुमान 6.7 प्रतिशत को सुभाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि भारत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। भारत के अपने विदेशी उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने सम्बंधित प्रयास आज सफल

होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि, अगस्त 2026 का माह भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत शानदार रहा है। वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियों के चलते भी भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 26.12 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है। अगस्त 2025 माह में भारत के कुल निर्यात 3,474 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे थे जो अगस्त 2026 में बढ़कर 4,381 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाइजेशन के अनुसार, भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में ही रही आकर्षक वृद्धि दर भारतीय निर्यातकों की ताकत, प्रतिस्पर्धा व बाजार के हिसाब से ढलने की क्षमता को दर्शाती है। चीन, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, स्पेन एवं श्रीलंका जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच भारत के निर्यात बास्केट के विस्तार का संकेत है। आटोमोबाइल निर्यात में 22.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है, इसमें दोपहिया व तिपाहिया वाहनों का दबदबा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में भी 3.14 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनीयरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि भारत की मजबूत स्थिति को दर्शा रही है।

विदेशी व्यापार के मामले में भारत विश्व में केवल कुछ देशों (अमेरिका सहित) पर निर्भर रहने के स्थान पर अब अपने विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए नए नए बाजार तलाश रहा है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों का सुपरिणाम दिखाई भी देने लगा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम पांच माह (अप्रैल-अगस्त 2026) के दौरान भारत का ब्रिक्स देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) को निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 1,990 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। इसी अवधि में चीन को भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 39 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज हुई है। ब्रिक्स समूह के समस्त सदस्य देशों के साथ भारत अपने आर्थिक एवं राजनैतिक सम्बंध लगातार मजबूत कर रहा है, जिसका परिणाम अब इन देशों के साथ भारत के लगातार बढ़ रहे विदेशी व्यापार के रूप में दिखाई देने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स के चार मुख्य देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान 8.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान 9.2 प्रतिशत हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच माह के दौरान चीन को 960 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस को भारतीय उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 58 प्रतिशत, 13 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज की गई है।

आज कई अमेरिकी कम्पनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं - एस्पू जेनेका, बैक ऑफ अमेरिका, टरूब्रिज, गाइडवायर, आदि। भारत में स्थापित इन वैश्विक योग्यता केंद्रों में हजारों की संख्या में भारतीय इंजीनीयर कार्य कर रहे हैं। कहीं यह अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगातार बदले जा रहे वीजा सम्बंधी नियमों के चलते तो नहीं हो रहा है। अमेरिकी नीतियों से केवल विश्व के अन्य देश ही नहीं बल्कि अमेरिकी कम्पनियां भी परेशानी महसूस करने लगी हैं एवं वे अपनी इकाइयों को भारत सहित अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही हैं।

भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ अपने सम्बंधों को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर नागरिकों को सनातन संस्कृति के संस्कारों से परिचित कराने के प्रयास भी भारत द्वारा किए जा रहे हैं ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परमपूज्य सर संघचालक डॉ मोहन भागवत जी ने हाल ही में अमेरिका, कनाडा एवं ब्रिटेन की 17 दिवसीय यात्रा सम्पन्न की है। इन देशों में आयोजित सर्व धर्म सभाओं में अन्य धर्मों के धर्माचारकों की भी उत्साहपूर्ण भागीदारी रही है। उक्त यात्रा में न्यूयार्क में सार्वभौमिक एकात्मता, टोरंटो में विश्व में मित्रता एवं लंदन में अपनेपन के संदेश के साथ डा भागवत ने सामाजिक समरसता, सेवा, विविधता के बीच एकता और नागरिक कर्तव्य पर भी जोर दिया। प्रवासी भारतीयों से उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा निभाने का आह्वान किया। एक तरफ भारत पूरे विश्व में सामंजस्य स्थापित कर शांति स्थापित करना चाहता है तो दूसरी ओर अमेरिका विभिन्न देशों पर अपने एकतरफा नियम थोपना चाहता है, चाहे वह टैरिफ से सम्बंधित हों अथवा अन्य देशों पर सैंक्शन लगाने से सम्बंधित हों।

क्यों घास के मैदानों बचाना, गैडों को बचाने के लिए जरूरी है?

इस परियोजना के तहत देश में घास के मैदान कितने बड़े क्षेत्र में हैं, उनकी हालत कैसी है, वहां कितनी तरह के जीव-जंतु और पौधे पाए जाते हैं, उन्हें कितना नुकसान हुआ है और वे पर्यावरण को क्या लाभ देते हैं—इन सभी बातों का अध्ययन किया जाएगा । इसमें घास के मैदानों की कार्बन क्षमता का भी आकलन होगा । इससे देश का एक राष्ट्रीय घासभूमि एटलस तैयार करने, किन इलाकों में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है यह तय करने और भविष्य के लिए बेहतर प्रबंधन दिशानिर्देश बनाने में मदद मिलेगी । इस तरह गैडों के संरक्षण और घास के मैदानों के संरक्षण की दोनों योजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं ।

(भुपेंद्र यादव) एक समय में एक सींग वाला गैंडा उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में पाया जाता था। इसका इलाका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास तक फैला हुआ था। आज भारत में गैंडों की जंगली आबादी मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। भारत के लिए एक सींग वाला गैंडा सिर्फ एक खास वन्यजीव नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र और तराई के बाढ़ वाले इलाकों और घास के मैदानों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है।एक समय में एक सींग वाला गैंडा उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में पाया जाता था। इसका इलाका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास तक फैला हुआ था। आज भारत में गैंडों की जंगली आबादी मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब गैंडों के आवास क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। हमारी गैंडा संरक्षण रणनीति इस समझ पर आधारित है कि संरक्षण का मतलब सिर्फ गैंडों की मौजूदा आबादी को सुरक्षित रखना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य उनके पुराने आवास क्षेत्रों में भी उनकी आबादी को बढ़ाना होना चाहिए। गैंडों की आबादी में निरंतर सुधार को देखते हुए मोदी सरकार ने 2019 में एक सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की। इसमें मौजूदा आबादी को मजबूत करने, पुराने और उपयुक्त इलाकों में गैंडों को फिर से बसाने, उनकी आनुवंशिक विविधता बनाए रखने, अलग-अलग आवासों को आपस में जोड़ने, वैज्ञानिक तरीके से गैंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने पर जोर दिया गया है। लेकिन भारत में गैंडे की कहानी सबसे बढ़कर उसके दोबारा बढ़ने की कहानी है। गैंडों की संख्या करीब 170 फीसदी बढ़ी है। सितंबर 2024 तक इनकी संख्या करीब 1,500 से बढ़कर 4,000 से

अधिक हो गई। आज भारत दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के माध्यम से चलाए जा रहे भारतीय गैंडा संरक्षण कार्यक्रम में गैंडों की वैज्ञानिक निगरानी, उनकी सुरक्षा, उनके रहने की जगहों को बेहतर बनाना, गैंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की योजना, इसानों और वन्यजीवों के बीच बेहतर तालमेल और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका एक अहम लक्ष्य बिहार और अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में भी गैंडों की आबादी बढ़ाना है, जहां उनके रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं।किसी एक वन्यजीव को बचाने का मतलब उसके पूरे प्राकृतिक वातावरण को बचाना भी है। गैंडा एक बड़ा शाकाहारी जानवर है। उसके लिए नदियों के किनारे के उपजाऊ मैदान, तराई के घास के मैदान और आर्द्रभूमियां बेहद जरूरी हैं। ये इलाके हिरण, जंगली भैंस, हाथी, बाघ, कई तरह के पक्षियों और कई छोटी प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, घास के मैदान स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हैं। इन्हें खराब होने, गंदत तरीके से वनस्पति परिवर्तन और बाहरी आक्रामक प्रजातियों के फैलाव से बचाने के लिए सक्रिय और वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत होती है। गैंडा संरक्षण कार्ययोजना में घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों का नक्शा तैयार करने और उनका आकलन करने, आक्रामक प्रजातियों की पहचान करने और अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

घास के मैदानों का भी आकलन – गैंडे पर केंद्रित इस प्रयास के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय पहल भी

चल रही है। 2026 से 2031 तक घास के मैदानों के लिए चलने वाले व्यापक आकलन के लिए 20.86 करोड़ रुपये खर्चे गए हैं। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और भारतीय वन सर्वेक्षण मिलकर लागू करेंगे। इस परियोजना के तहत देश में घास के मैदान कितने बड़े क्षेत्र में हैं, उनकी हालत कैसी है, वहां कितनी तरह के जीव-जंतु और पौधे पाए जाते हैं, उन्हें कितना नुकसान हुआ है और वे पर्यावरण को क्या लाभ देते हैं—इन सभी बातों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें घास के मैदानों की कार्बन क्षमता का भी आकलन होगा। इससे देश का एक राष्ट्रीय घासभूमि एटलस तैयार करने, किन इलाकों में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है यह तय करने और भविष्य के लिए बेहतर प्रबंधन दिशानिर्देश बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह गैंडे के संरक्षण और घास के मैदानों के संरक्षण की दोनों योजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गैंडों के संरक्षण में जलवायु परिवर्तन के असर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। काजीरंगा जैसे इलाकों में बाढ़ प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन मौसम की चरम घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनकी तीव्रता आने वाले समय में वन्यजीवों के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है। ऐसे में यह जरूरी होगा कि गैंडों के पास ऊंचे इलाकों तक पहुंचने के रास्ते हों। उनके अलग-अलग आवासों के बीच संपर्क बना रहे और उनके आने-जाने के रास्ते सुरक्षित रहे। इसके साथ ही पूरे प्राकृतिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर आवासों का प्रबंधन करना भी जरूरी होगा। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति में भी जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने को गैंडों के लंबे समय के संरक्षण का हिस्सा बनाया गया है।

जमीन पर काम करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका – गैंडों की सुरक्षा में तकनीक का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक निगरानी व्यवस्था, उनके स्थान और गतिविधियों पर नजर रखने वाली तकनीक,

पशु चिकित्सा जांच, आनुवंशिक तकनीक और बेहतर फैसले लेने में मदद करने वाली प्रणालियां वन्यजीव संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को और मजबूत कर सकती हैं। लेकिन तकनीक के बावजूद मैदान में काम करने वाले लोगों वन भूमिका सबसे अहम बनी रहती है। वन रक्षक, निगरानीकर्मी, हाथियों के महावत, पशु चिकित्सक और मैदानी अधिकारी हर दिन जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। यही लोग संरक्षण व्यवस्था की असली आंखें हैं। इसलिए विश्व गैंडा दिवस इन लोगों के काम और समर्पण को याद करने का भी मौका है। गैंडों के आवास के आसपास रहने वाले समुदाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रजाति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि संरक्षण को केवल सरकार का काम न मानकर साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए।भारत के अनुभव ने यह भी दिखाया है कि राज्यों और देशों की सीमाओं से आगे सहयोग कितना जरूरी है। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में गैंडे की आबादी वाले अन्य एशियाई देशों की बैठक हुई थी, जिसमें भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल शामिल हुए थे। इन देशों ने मिलकर एशियाई गैंडों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सहयोग मजबूत करने वाली नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। इस विश्व गैंडा दिवस पर हम अब तक की यात्रा पर संतोष जता सकते हैं कि एक ऐसी प्रजाति को कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी, आज लगातार बढ़ रही है। एक सींग वाला गैंडा हमें याद दिलाता है कि अगर समाज जुड़ संकल्प के साथ कदम उठाए तो किसी प्रजाति की गिरती संख्या को फिर से बढ़ाया जा सकता है। गैंडों की रक्षा करके हम उन नदियों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों, जंगलों और समुदायों की भी रक्षा कर रहे हैं, जो मिलकर भारत के इन इलाकों को देश के सबसे समृद्ध प्राकृतिक खजानों में शामिल करते हैं।गैंडे की वापसी देश की उपलब्धि है। इसका भविष्य देश की जिम्मेदारी है।



संक्षिप्त

समाचार

यूएसविदेशविभागका बड़ा बयान: अंतिम चरण में पहुंचा भारत-अमेरिका व्यापार सौदा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों देश इस समझौते के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को पूरा कर चुके हैं और अब केवल कुछ अंतिम बारीक विवरणों को सुलझाना बाकी है। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक ऐसा नया स्तर और गति मिलेगी, जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई है। व्यापार हमेशा से भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में सबसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। पीटीआई के एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ‘व्यापारिक मोचे पर यह समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगा, दोनों देशों के बीच व्यापारिक नीतियां हमेशा से एक बड़ा गतिरोध रही हैं। लेकिन अब हम इसके बेहद करीब हैं और बहुत जल्द इस संबंध में एक बड़ी और रोमांचक घोषणा देखने को मिल सकती है।’ यह बड़ी आर्थिक कुटनीतिक सफलता ऐसे समय में आ रही है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अक्टूबर 2026 में भारत का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान कई बड़े और रणनीतिक समझौतों की आधिकारिक घोषणाएं की जा सकती हैं। यह साल भारत और अमेरिका के राजनयिक इतिहास में बेहद असाधारण रहा है। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्री एक ही वर्ष में तीसरी बार मिलने जा रहे हैं, जो ववादेशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।

इसके अलावा, मई 2027 में नई दिल्ली ‘क्वाड’ विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भी अमेरिका और भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। गति थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता आते ही आईएमईसी कॉरिडोर का काम बेहद तेजी से आगे बढ़ेगा।

बाजार की अनिश्चिता के चलते प्रेस्टीज ग्रुप ने आतिथ्य कारोबार का 2,700 करोड़ रुपए का आईपीओ लाला

नई दिल्ली, एजेंसी। रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स ने बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों और अन्य वजहों का हवाला देते हुए अपने होटल कारोबार के आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सहायक इकाई प्रेस्टीज होस्पिटैलिटी वेचर्स लिमिटेड (पीएचवीएल) ने आईपीओ लाने के लिए पिछले साल अप्रैल में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) जमा किया था। कंपनी की सार्वजनिक निगम के जरिए 2,700 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना थी। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि निदेशक मंडल ने ‘‘रणनीतिक विचारों और बाजार की अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए डीआरएचपी वापस लेने’’ का निर्णय लिया है। पीएचवीएल बाजार की अनुकूल परिस्थितियों, आवश्यक मंजूरियों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अपने इक्विटी शेयरों के आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष नए सिर से मसौदा दस्तावेज दाखिल करने पर विचार कर सकती है। इस साल अगस्त में प्रेस्टीज एस्टेट्स ने बताया था कि कनाडा की निवेश फर्म सीपीपीआईबी उसकी आतिथ्य शाखा में 3,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। बेंगलुरु स्थित प्रेस्टीज एस्टेट्स देश के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। यह प्रमुख शहरों में आवास, कार्यालय, मॉल और होटल विकसित करती है। कंपनी के पास कई होटल हैं।

मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के दम पर वैश्विक संकटों से मजबूती से लड़ रहा है भारत: आरबीआई बुलेटिन

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा बुलेटिन में प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ लेख के अनुसार, भारत के वित्तीय और बाहरी क्षेत्र घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण बेहद सुरक्षित और सुदृढ़ स्थिति में हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने चेतावनी भी दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और मौसम की अनिश्चितताएं आने वाले समय में देश के लिए बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं।

सितंबर महीने में पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, तेल महंगा होने से दुनिया भर की स्प्लाइं चैन बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। इससे भारत के भीतर भी महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। इसके अलावा, दुनिया की बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से उनके सरकारी खजाने पर दबाव देखा जा रहा है, जिसका थोड़ा-बहुत असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है।

इन तमाम अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था

ने शानदार सकल घरेलू उत्पाद विकास दर दर्ज की है। लेख में स्पष्ट किया गया है कि देश का वास्तविक आर्थिक आधार इतना मजबूत है कि वह बाहरी झटकों को



आसानी से झेल रहा है। अगस्त और सितंबर के दौरान देश के शेयर बाजारों में सुस्ती जरूर देखी गई, क्योंकि वैश्विक तनाव और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण निवेशकों ने फ्रूक-फ्रूक कर कदम रखा। इसके चलते सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले, जबकि अगस्त में उन्होंने जमकर निवेश किया था।

भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूती इसका विदेशी मुद्रा

त्योहारी सीजन से ठीक पहले महंगे हुए सोना-चांदी

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आज आप सोने-चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं। शुक्रवार 25 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। ग्लोबल बैंक यह दावा कर रहे हैं कि दिवाली तक सोने के दाम आसमान छू सकते हैं। वहीं चांदी को लेकर ब्रू



ने दावा किया है कि चांदी के दाम तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में आज ग्लोबल और घरेलू बाजार के रेट्स क्या हैं और स्खड़ पर सोना कहां ट्रेड कर रहा है, ये जानते हैं। मल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज (स्खड़) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध 150 यानी 0.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,50,860 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय ज्वेलर्स की ओर से आई मजबूत हाजिर मांग के बाद बाजार सहभागियों द्वारा नई पोजीशन बनाने के कारण सोने की कीमतों में यह सुधार देखा गया है। दूसरी ओर, वैश्विक मंच पर भी तेजी रही और न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.01 प्रतिशत बढ़कर 4,275.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

क्रेडिट-लाइफ इंश्योरर्स की बल्ले-बल्ले: आईआरडीएआई के नए नियमों से इन बीमा कंपनियों को मिलेगा फ़ायदा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय बीमा नियामक द्वारा इंश्योरंस एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन में कटौती के प्रस्तावित नियमों से लाइफ इंश्योरंस कंपनियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन लाइफ इंश्योरंस कंपनियों का क्रेडिट-लाइफ बिजनेस ज्यादा है, उन्हें कमीशन की प्रस्तावित कम दरों से फ़ायदा हो सकता है। सेंट्रम की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लाइफ इंश्योरंस कंपनियों के ‘एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवैलेंट’ में क्रेडिट-लाइफ बिजनेस का हिस्सा ज्यादा है, उन्हें इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा कमीशन दरों में प्रस्तावित बदलावों से फ़ायदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्तावित

नियमों से पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कमीशन का भुगतान कम हो सकता है



खर्चों पर ज्यादा सख्ती से नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, ‘हमारा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कमीशन की कम दरों से फ़ायदा

होगा, खासकर उन कंपनियों को जिनका एपीई में क्रेडिट-लाइफ का हिस्सा ज्यादा

हो सकता है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, क्रेडिट-लाइफ प्रोडक्ट्स के लिए कमीशन दरें घटाकर 2 प्रतिशत की जा सकती हैं। प्रतिशत कर दी जाएगी। सेंट्रम ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाली कम लागत वाली इंश्योरेंस कंपनियां आखिरकार अपने खर्च के स्तर को लगभग 10 प्रतिशत तक ला सकती हैं। खर्च की नई सीमाओं को लागू करने के लिए, कमीशन का भुगतान प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर, पॉलिसी की अवधि और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आधार पर तय किया जाएगा। प्रस्तावित कमीशन दरें 10 साल या उससे ज्यादा समय की लंबी अवधि वाली पॉलिसी बेचने वाले व्यक्तिगत एजेंटों के लिए 25 प्रतिशत से लेकर सिंगल-प्रीमियम पॉलिसी के लिए 2-10 प्रतिशत तक हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कमीशन के हिसाब से खुद को ढालेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बदलावों से कंपनियां रिटेल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने, खर्च कम रखने और अपनी बिजनेस रणनीतियों में बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कमीशन के हिसाब से खुद को ढालेंगे। सेंट्रम ने कहा, ‘संरचनात्मक रूप से, हमें उम्मीद है कि कंपनियां रिटेल प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देंगी, खर्च कम रखेंगी और कुछ कैटेगरी में वॉल्यूम कम देखेंगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कमीशन के हिसाब से खुद को ढालेंगे।’ ‘एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट’ की सीमा को स्खड़28 से शुरू होने वाले दो वर्षों के भीतर ‘ग्रांस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम’ के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।

शीर्ष नौ शहरों में जुलाई-सितंबर के बीच आवास बिक्री 6 प्रतिशत घटकर 1.03 लाख इकाई पर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के नौ प्रमुख शहरों में आवास बिक्री जुलाई-सितंबर तिमाही में छह प्रतिशत घटकर 1.03 लाख इकाई रह गई। रियल एस्टेट के आंकड़ों का अवलोकन करने वाली कंपनी प्रॉपइक्विटी ने यह जानकारी दी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी घर खरीदने की धारणा को प्रभावित किया है। प्रॉपइक्विटी ने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता के प्राथमिक आवासीय बाजारों के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही में इन नौ शहरों में आवास बिक्री 1,03,170 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,09,420 इकाई थी। समीक्षाधीन तिमाही में नए घरों की आपूर्ति घटकर 98,165 इकाई रह गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,00,330 इकाई की नई आपूर्ति हुई थी। आमतौर पर जुलाई-सितंबर तिमाही में कारणांतर के कारण आवास बिक्री में



धीमी रहती है। बारिश के चलते रियल एस्टेट डेवलपर नयी परियोजनाएं शुरू करने से बचते हैं।

वहीं, दिसंबर तिमाही में त्योहारी मांग बढ़ने से बिक्री में सुधार आता है। इस मांग का लाभ उठाने के लिए डेवलपर नई आपूर्ति बढ़ाने के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न

प्रोत्साहन भी देते हैं। इन प्रमुख शहरों में से बेंगलुरु में बिक्री एक प्रतिशत बढ़कर 17,340 इकाई हो गई, जो पिछले साल 17,170 इकाई थी। हैदराबाद में बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 15,470 इकाई रही, जबकि पिछले साल यह 13,890 इकाई थी। मुंबई में आवास बिक्री आठ प्रतिशत घटकर 9,830 इकाई रही।

बिक्री 12 प्रतिशत घटकर 8,090 इकाई रही

मुंबई महानगर क्षेत्र के ठाणे में बिक्री जुलाई-सितंबर तिमाही में 11 प्रतिशत घटकर 16,230 इकाई रही, जबकि नवी मुंबई में बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 9,810 इकाई हो गई। पुणे में आवास बिक्री 16 प्रतिशत घटकर 17,860 इकाई रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 21,190 इकाई थी। दिल्ली-एनसीआर में बिक्री 12 प्रतिशत घटकर 8,090 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,230 इकाइयां थीं। चेन्नई में आवास बिक्री 17 प्रतिशत घटकर 4,680 इकाई रह गई, जबकि पिछले साल यह 5,640 इकाई थी। कोलकाता में भी आवास बिक्री 17 प्रतिशत घटकर 3,860 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 4,640 इकाई थी। प्रॉपइक्विटी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर जसूजा ने कहा कि शीर्ष श्रेणी के शहरों में आवासीय संपत्तियों की नई आपूर्ति और बिक्री अब भी तिमाही आधार पर करीब एक लाख इकाइयों के आसपास बनी हुई है।

एडरॉयट इंडस्ट्रीज के आईपीओ को 177 गुना बोली मिली

नई दिल्ली, एजेंसी। एडरॉयट इंडस्ट्रीज के आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) को शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन करीब 177 गुना अभिधान मिला। इसके साथ ही चार सार्वजनिक निगम अधिक अभिधान के साथ बंद हुए। अन्य तीन आईपीओ स्वास्तिका इंफ्रा, एलिवेट कैम्पसेज और आरमी इफोटेक के हैं। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, एडरॉयट इंडस्ट्रीज के 151 करोड़ रुपए के आईपीओ में 78,72,900 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 1,39,22,95,200 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। इस तरह आईपीओ 176.85 गुना अभिधान हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 332.35 गुना, पात्र संस्थागत खरीदारों (व्यूआईबी) के हिस्से को 195.04 गुना और खुदरा निवेशकों के हिस्से को 99.81 गुना अभिधान मिला। एडरॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के आईपीओ का मूल्य दायरा 126-134 रुपए प्रति शेयर है। इसमें 98,97,000 तक नए इक्विटी शेयरों का निर्गम और 13,50,000 तक इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधाएं और किंगडार्मन से 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा से जुड़ी कंपनी एलिवेट कैम्पसेज के 2,100 करोड़

रुपए के आईपीओ को शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 1.79 गुना अभिधान मिला। इसे



3,36,73,468 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 6,02,86,769 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। एलिवेट कैम्पसेज के आईपीओ में नए इक्विटी शेयरों का निर्गम शामिल है और बिक्री पेशकश का कोई हिस्सा नहीं है। इसका मूल्य दायरा 343-362 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ऊपरी मूल्य दायरे पर कंपनी का मूल्यांकन 6,100 करोड़ रुपए से अधिक होगा। स्वास्तिका इंफ्रा के 161 करोड़ रुपए के आईपीओ को शुक्रवार को 7.60 गुना अभिधान मिला।

रायपुर पहुंचे नए कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत, भाजपा सरकार पर बोला हमला: ‘हसदेव’, ‘बेरोजगारी’ और ‘SIR’ को लेकर दागे 10 सवाल

रायपुर (जनता के गोट)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी व सांसद सुखदेव भगत के प्रथम रायपुर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक ऐतिहासिक स्वागत किया। इसके पश्चात राजीव भवन में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी सुखदेव भगत ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ‘जल, जंगल, जमीन’, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर 10 तीखे सवाल दागे।

हसदेव और आदिवासियों के अधिकारों पर कॉपोरेट हित हावी
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि हसदेव अरण्य समेत कई इलाकों में ग्राम सभा की सहमति को नजरअंदाज कर जंगल काटे जा रहे हैं।



उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिजों का ‘वेयरहाउस’ नहीं है; यहां आदिवासी रहते हैं। जंगल कटेंगे तो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भविष्य कटेगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल के लिए आवंटित खदानों का 9 साल में ही अंशार्ध दोहन कर दिया गया है।

6.1% बेरोजगारी दर और ‘SIR’ से कटे नामों पर मांगा जवाब

कांग्रेस ने राज्य में युवाओं की स्थिति पर PLFS (2025) की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 15-29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत पहुंच चुकी है। सरकारी भर्तियां अटकती हैं और युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। वहीं, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के बाद फरवरी 2026 में जारी मतदाता सूची पर सवाल उठते हुए कांग्रेस ने मांग की कि विधानसभावार हटाए गए 1.87 करोड़ मतदाताओं में से निष्कासित नामों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि पता चले कि इसमें कितने आदिवासी और गरीब मजदूर शामिल हैं।

जिगड़ती कानून-व्यवस्था और मन्रेगा पर CAG की रिपोर्ट
पत्रकार वार्ता में राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और रेत की अवैध वसूली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इसके अलावा,



मन्रेगा (स्वहन्त्र) पर आई सीएजी (छत्र) की 2026 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सरकार से ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ज़क़) सार्वजनिक करने की मांग की गई।
सड़क से सदन तक लड़ाई और 2028 का संकल्प
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुखदेव भगत के पास झारखंड का लंबा राजनीतिक अनुभव है और

उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर 2028 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएगी।
दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी
पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री

टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश सह-प्रभारी जरिता लैतफांग, विजय जांगिड़, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू, मो. अकबर, मोहन मरकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सांसद भूतोदेवी नेताम, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैडू और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व विधायक उपस्थित थे।

प्रयास हॉस्टल के बच्चों के द्वार पहुंची एमएमयू: 468 लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए टिप्स

रायपुर (जनता के गोट)। छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर सड्डू स्थित प्रयास हॉस्टल में रहने वाले बच्चों और छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) की दो टीमों ने हॉस्टल परिसर में ही पहुंचकर बच्चों एवं अन्य लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, डॉक्टरों परामर्श दिया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया।

468 लोगों की जांच, 19 लैब टेस्ट और मुफ्त दवा वितरण
शिविर में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फर्मासिस्ट सहित पूरी मेडिकल टीम मौजूद रही। विशेष स्वास्थ्य शिविर में कुल 468 लोगों की ओपीडी जांच की गई, जिनमें प्रयास हॉस्टल के 110 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद 463 जरूरतमंद मरीजों को



मौके पर ही आवश्यक दवाइयां दी गईं। वहीं, मरीजों की सटीक स्थिति का आकलन करने के लिए 19 लैब टेस्ट भी मौके पर ही किए गए।
मानसून जनित बीमारियों और स्वच्छता पर दिया गया जोर
उपचार के साथ-साथ शिविर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मेडिकल टीम ने छात्रों को बारिश के मौसम में फैलने वाली बीमारियों—जैसे डेंगू, मलेरिया और जलजनित रोगों—से बचाव के तरीके समझाए।

रायपुर/दुर्ग (जनता के गोट)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत भिलाई सेक्टर-7 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों को सम्मानित करने के साथ-साथ दुर्ग स्थित ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

‘विकसित भारत’ के निर्माण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम
‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और आशा (मितानिन) कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा-संकल्प के अनुरूप पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही हैं। वे न केवल शासन की कल्याणकारी योजनाओं



को जन-जन तक पहुंचा रही हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पोषण माह का उल्लेख करते हुए स्वच्छता, पौष्टिक आहार और नियमित टीकाकरण पर जोर दिया और कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों को भी आंगनबाड़ी केंद्रों से निरंतर जुड़कर कार्यकर्ताओं का सहयोग करना चाहिए।
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया

सहायता तथा अस्थायी आश्रय की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संकटग्रस्त महिलाओं को समय पर सुरक्षा, पुनर्वास और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सेंटर की व्यवस्थाओं और साफ-सफाई पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने केंद्र के स्टाफ के कार्यों की सराहना की।
वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद इन कार्यक्रमों में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महिला मोर्चा भिलाई अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, वरिष्ठ नागरिक सुरेंद्र कौशिक व पुरुषोत्तम देवानग, महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार साहू, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अशोक शर्मा (पांडे) सहित विभागीय पर्यवेक्षक, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं और हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़: शिक्षा विभाग में 6,812 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, व्यापम कराएगा ऑनलाइन CBT परीक्षा



5,000 नियमित और 1,812 सविदा पदों पर होगी नियुक्ति, 11 अक्टूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं
रायपुर (जनता के गोट)। छत्तीसगढ़ के शासकीय और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कुल 6,812 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डे ने शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह भर्ती युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

5,000 नियमित और 1,812 सविदा पदों पर भर्ती
श्रीमती पाण्डे ने बताया कि कुल 6,812 पदों में से 5,000 पद शासकीय स्कूलों में नियमित रूप से भरे जाएंगे, जो युवाओं को सुरक्षित और दीर्घकालिक करियर प्रदान करेंगे। वहीं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 1,812 सविदा पदों पर नियुक्तियों की जा रही हैं।

व्यापम कराएगा केंद्रीकृत ऑनलाइन परीक्षा
नियमित पदों पर परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर पूर्व में होने वाले विवादों और विलंब को समाप्त

छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल एवं रायपुर डाक संभाग ने नरैया तालाब में चलाया विशेष स्वच्छता अभियान

रायपुर। स्वच्छ भारत अभियान 6.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल एवं रायपुर डाक संभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर के नरैया तालाब परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नागरिकों को अपने आसपास के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था।

स्वच्छता अभियान में बंच ऑफ पुल एनजीओ की टीम ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। एनजीओ के स्वयंसेवकों ने डाक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर श्रमदान किया तथा नरैया तालाब परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।



इस अवसर पर श्री एन. के. राजपाल, सहायक निदेशक, छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक

करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से अपने घर, कार्यस्थल तथा आसपास के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों में सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, स्वच्छ व्यवहार तथा सामुदायिक सहभागिता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

NIT रायपुर में ‘ट्रैफिक हैकेथॉन 2026’ का फाइनल राउंड संपन्न

- पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने युवाओं के प्रोजेक्ट्स को सराहा, व्यवस्थाओं में लागू होंगे उपयोगी सुझाव

रायपुर (जनता के गोट)। रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से आयोजित Traffic Hackathon 2026 का अंतिम प्रस्तुतीकरण (फाइनल राउंड) रविवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस कमिश्नर रायपुर के तत्वावधान में आयोजित इस हैकेथॉन में दो चरणों की स्क्रूटनी के बाद चयनित शीर्ष 37 टीमों ने अपने-अपने तकनीकी समाधान पेश किए।

पुलिस कमिश्नर ने परखे युवाओं के नवाचार कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) और पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं प्रोटोकॉल) डॉ. अर्चना झा ने सभी स्टॉलों और प्रस्तुतियों का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने युवाओं से उनके प्रोजेक्ट्स की कार्यप्रणाली समझी और यातायात की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने वाले नवाचारों की जमकर सराहना की।
विशेषज्ञ जूरी मंडल ने किया मूल्यांकन- प्रतिभागियों के प्रोजेक्ट्स के निष्पक्ष और तकनीकी आकलन के लिए विशेषज्ञ निर्णायक मंडल (जूरी) का गठन किया गया था। इसमें डॉ.



के. प्रधान (Retd. E-in-C, PWD), शशील राय श्रीवास्तव (E-in-C, NRDA), डॉ. सनी देओल (एसोसिएट प्रोफेसर, NIT), एस. एन. पाठक (E& DGM, SAIL), श्रीमती श्रेलिल साहू (ACP, यातायात) एवं गुरजीत सिंह (DSP) शामिल रहे। इसके साथ ही The Institution of Engineers

(India) के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी अपना विशेष मार्गदर्शन दिया।
इन 6 प्रमुख विषयों पर पेश किए गए समाधान- हैकेथॉन के तहत प्रतिभागियों ने रायपुर की वास्तविक ट्रैफिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 6 प्रमुख श्रेणियों में अपने मॉडल प्रस्तुत किए: - यातायात अभियांतिकी एवं प्रबंधन: सुगम आवाजाही के लिए बेहतर डिजाइन व मैनेजमेंट। - पार्किंग प्रबंधन: शहर में पार्किंग समस्या से निपटने के डिजिटल तरीके। - गैर-मोटर चालित परिवहन: साइकिलिंग और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर। - सार्वजनिक परिवहन एकीकरण: पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक सुलभ बनाने के उपाय। - सुरक्षा एवं

जाम/भीड़भाड़ समाधान: दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और बॉटलनेक से मुक्ति के मॉडल। - AI एवं IoT का उपयोग: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर आधारित स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। शीघ्र होगी विजेताओं की घोषणा, धरातल पर उतरेंगे सुझाव जूरी और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चयनित उत्कृष्ट व व्यावहारिक नवाचारों के आधार पर विजेताओं की घोषणा जल्द की जाएगी। एक विशेष समारोह आयोजित कर विजेता टीमों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। रायपुर पुलिस प्रशासन के अनुसार, हैकेथॉन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सुझावों का गहन विश्लेषण कर उन्हें आने वाले समय में रायपुर शहर की यातायात प्रणाली में सुधार के लिए धरातल पर लागू किया जाएगा।